

मेक इन इंडिया के आठ वर्ष

प्रलम्बिस के लयि:

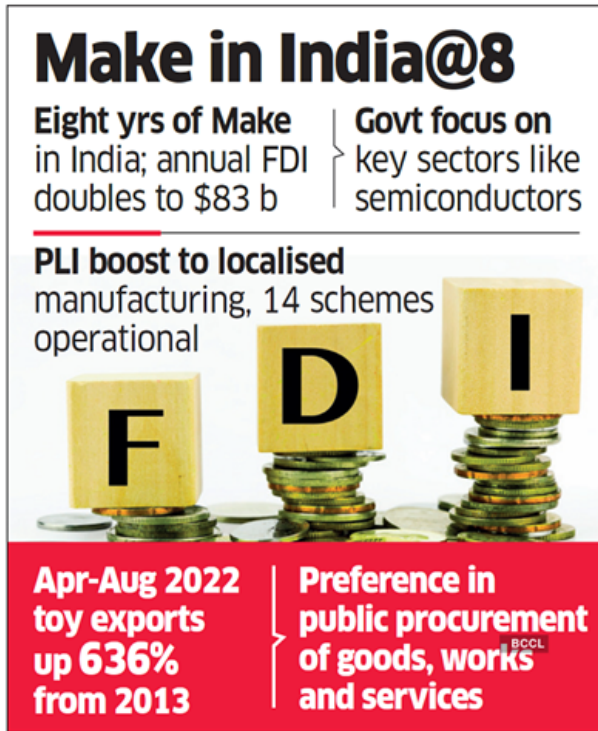
मेक इन इंडिया, प्रत्यक्ष वदिशी नविश, ईज ऑफ डूइंग बजिनेस, प्रोडक्शन लकिड इंसेंटवि (PLI), नेशनल सगिल वडिो ससि्टम (NSWS), एक ज़लिा-एक उत्पाद (ODOP) ।

मेन्स के लयि:

भारतीय अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने में मेक इन इंडिया का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

मेक इन इंडिया ने आठ वर्ष के पथ-प्रदर्शक सुधार कर लिये हैं और वर्ष 2022 में वार्षिक प्रत्यक्ष वदिशी नविश दोगुना होकर 83 बलियिन अमेरिकी डॉलर हो गया है ।



मेक इन इंडिया कार्यक्रम:

- परचिय:
 - वर्ष 2014 में लॉन्च कयि गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक वनिर्माण और नविश गंतव्य में बदलना है ।
 - यह पहल दुनिया भर के संभावित नविशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला नर्मिर्ण है ।
 - मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं । इनमें वनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं ।
- उद्देश्य:

- नए औद्योगीकरण के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिये भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना।
- मध्यावधि में वनरिमाण क्षेत्र की वृद्धि को 12-14% वार्षिक करने का लक्ष्य।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में वनरिमाण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना।
- वर्ष 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
- नरियात आधारित विकास को बढ़ावा देना।

■ परणाम:

- FDI अंतरवाह: 2014-2015 में भारत में FDI अंतरवाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से लगातार आठ वर्षों में रिकॉर्ड FDI प्रवाह तक पहुँच गया है।
 - वर्ष 2021-22 में 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI दर्ज किया गया।
 - हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की वजह से भारत चालू वित्त वर्ष (2022-23) में FDI में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आकर्षित करने की राह पर है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में खलौनों का आयात 70% घटकर (877.8 करोड़ रुपए) हो गया है। भारत के खलौनों के नरियात में अप्रैल-अगस्त 2022 में 2013 की इसी अवधि की तुलना में 636% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।
- प्रोडक्शन लिक्विडिटी इंसेंटिव (PLI): 14 प्रमुख वनरिमाण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिक्विडिटी इंसेंटिव (PLI) योजना 2020-21 में मेक इन इंडिया पहल को एक बड़े बढ़ावा के रूप में शुरू की गई थी।

मेक इन इंडिया योजना में सहायक पहल:

■ राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली (NSWS):

- राष्ट्रीय एकल खड़िकी प्रणाली (NSWS) का सितंबर 2021 में शुभारंभ किया गया ताकि निवेशकों को अनुमोदन और मंजूरी के लिये एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके व्यापार करने में आसानी हो।
- इस पोर्टल ने निवेशकों के अनुभव को बढ़ाने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई मौजूदा नकिसी प्रणालियों को एकीकृत किया है।

■ गतिशक्ति:

- सरकार ने देश में वनरिमाण क्षेत्रों के लिये मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी हेतु एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसे प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम कहा जाता है। यह कनेक्टिविटी में सुधार करने वाले बुनियादी ढाँचे के नरिमाण के माध्यम से व्यावसायिक संचालन में ढुलाई-संबंधी दक्षता सुनिश्चित करेगा।

■ एक ज़िला एक उत्पाद योजना (ODOP):

- इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले को स्वदेशी उत्पादों के प्रचार और उत्पादन की सुविधा प्रदान करना तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के कारीगरों और नरिमाताओं को एक वैश्विक मंच प्रदान करना है, जिससे देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

■ खलौना नरियात में सुधार और आयात को कम करना:

- नमिन गुणवत्ता और खतरनाक खलौनों के आयात को संबोधित करने तथा खलौनों के घरेलू वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा बुनियादी सीमा शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% करने, गुणवत्ता नयितरण आदेश का कार्यान्वयन, आयातित खलौनों का अनिवार्य नमूना परीक्षण, घरेलू खलौना नरिमाताओं को 850 से अधिक बीआईएस लाइसेंस देने, खलौना क्लस्टरों के विकास आदि जैसे कई रणनीतिक हस्तक्षेप किये गए हैं।

■ अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु योजना:

- विश्व अर्द्धव्यवस्था में अर्द्धचालकों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने भारत में एक अर्द्धचालक, प्रदर्शन और डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित मुद्दे:

- शेल कंपनियों से निवेश: भारतीय एफडीआई का बड़ा हिस्सा न तो विदेशी है और न ही प्रत्यक्ष बल्कि मॉरीशस स्थिति शेल कंपनियों से आता है, जिनके बारे में संदेह है कि वे केवल भारत से काले धन का निवेश कर रहे हैं, जो मॉरीशस के माध्यम से भेजा जाता है।
- कम उत्पादकता: भारतीय कारखानों की उत्पादकता कम है और श्रमिकों के पास अपर्याप्त कौशल है।
 - मैकजि की रिपोर्ट में कहा गया है कि वनरिमाण क्षेत्र में भारतीय श्रमिक थर्डलैंड और चीन में अपने समकक्षों की तुलना में औसतन लगभग चार से पाँच गुना कम उत्पादक हैं।
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ: पैमाने की वांछित अर्द्धव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, आधुनिक उपकरणों में निवेश करने तथा आपूर्ति शृंखला विकसित करने के लिये औद्योगिक इकाइयों का आकार छोटा है।
- बुनियादी ढाँचा: भारत और चीन में वदियुत की लागत लगभग समान है, लेकिन भारत में वदियुत की कटौती बहुत अधिक है।
- परिवहन: चीन में औसत गति लगभग 100 कमी. प्रति घंटा है, जबकि भारत में यह लगभग 60 कमी. प्रति घंटा है। भारतीय रेलवे संतृप्त हो गया है और बहुत से एशियाई देशों के लिये भारतीय बंदरगाहों का प्रदर्शन बेहतर किया गया है।
 - विश्व बैंक के वर्ष 2018 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) ने 160 देशों में भारत को 44वाँ स्थान दिया। सिंगापुर सातवें, चीन को 26वें और मलेशिया को 41वें स्थान पर रखा गया। सिंगापुर में जहाज़ का औसत टर्नअराउंड समय एक दिन से भी कम था और भारत में यह 2.04 दिन था।
- लालफीताशाही: नौकरशाही प्रक्रियाएँ और भ्रष्टाचार भारत को निवेशकों के लिये कम आकर्षक बनाते हैं।

आगे की राह

- मेक इन इंडिया पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कदम में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र भारत में व्यापार करने वाले नविकर्तों के लिये अनुकूल है और राष्ट्र के वृद्धि एवं विकास में योगदान दे।
- यह कई सुधारों के माध्यम से संभव हुआ है जिससे नविकर्ता प्रवाह में वृद्धि हुई है और साथ ही आर्थिक विकास भी हुआ है।
- इस पहल के अंतर्गत भारत में व्यवसायों का लक्ष्य है कि जो उत्पाद 'मेक इन इंडिया' हैं, वे 'मेड फॉर द वर्ल्ड' भी हैं, जो गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????:

प्रश्न. वनरिमाण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हालिया नीतगत पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय नविकर्ता और वनरिमाण क्षेत्रों की स्थापना
2. 'सगिल वडि क्लीयर्स' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधगिरहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

- **राष्ट्रीय नविकर्ता और वनरिमाण क्षेत्र एक नई अवधारणा है** जो राष्ट्रीय वनरिमाण नीति, 2011 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय वनरिमाण नीति वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये नामित क्षेत्रों का चयन करने हेतु लागू किया जाने वाला एक नीति उपकरण है। **अतः 1 सही है।**
- इसके तहत 'सगिल वडि क्लीयर्स' की सुविधा प्रदान की गई है, जो लालफीताशाही को कम करेगा और देश में नविकर्ता एवं व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करेगा। **अतः 2 सही है।**
- प्रौद्योगिकी अधगिरहण और विकास कोष (TADF) को राष्ट्रीय वनरिमाण नीति के तहत लॉन्च किया गया था। TADF सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) द्वारा भारत अथवा विश्व स्तर पर बाजार में उपलब्ध प्रौद्योगिकी/अनुकूलित उत्पादों/वशिष्ट सेवाओं/पेटेंट/औद्योगिक डिज़ाइन के रूप में स्वच्छ, हरित तथा ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के अधगिरहण की सुविधा के लिये एक नई योजना है। **अतः 3 सही है।**
- इसका उद्देश्य "मेक इन इंडिया" के राष्ट्रीय फोकस में योगदान करने के लिये MSME क्षेत्र में वनरिमाण विकास को उत्प्रेरित करना है। **अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।**

??????:

प्रश्न. "मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता 'कौशल भारत' (Skill India) कार्यक्रम की सफलता और क्रांतिकारी श्रम सुधारों पर निर्भर करती है।" तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिये। (2019)